SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

उत्तर कोविड और ग्रामीण अर्थवयवस्था का सशक्तिकरण

रेखा चौबे, समाजशास्त्र विभाग,
एस. एन. सेन. बालिकास्नात्कोत्तर महाविद्यालय, कानपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author :
रेखा चौबे, समाजशास्त्र विभाग,
एस. एन. सेन बालिकास्नात्कोत्तर महाविद्यालय,
कानपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 16/07/2020
Revised on : -----
Accepted on : 22/07/2020
Plagiarism : 01% on 16/07/2020

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 1%

Date: Thursday, July 16, 2020
Statistics: 35 words Plagiarized / 2854 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

mÙkj dksfoM vkSj xzkeh.k vFkZo;oLFkk dk l'kfädj.k "kks/k lkjka"k % dksfoM&19 us oSf'od Lrj ij lekt ds gj {ks= dks çHkkfor fd;k ftlesa vFkZO;oLFkk dks bl gn rd /oLr dj fn;k gS fd dksbZ Hkh jk"Vª viuh vFkZO;oLFkk dks ugha lEHkky ik jgk gSA phuh ok;jl ds dkj.k

शोध सारांश :

कोविड–19 ने वैश्विक स्तर पर समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित किया जिसमें अर्थव्यवस्था को इस हद तक ध्वस्त कर दिया है कि कोई भी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं सम्भाल पा रहा है। चीनी वायरस के कारण पूरा विश्व आज एक ऐसे दौर मे पहुच गया है जहा उसके सामने अपने लोगों को महामारी के संक्रमण से सुरक्षित करना प्राथमिकता है। भारत मे भी यह संक्रमण बहुत तेजी से फैलने लगा जिसके कारण लॉक डाउनजैसा कठिन निर्णय लेना पडा। जब लोगो के सामने रोजगार और आय की समस्या उत्पन्न हो गयी। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न राज्यो से प्रवासी श्रमिकों का पलायन शुरू होगया। जिनको पुनः रोजगार मे लगाने की एक विकराल समस्या सरकार के सामने खडी हो गयी। प्रस्तुत प्रपत्र का उद्देशय कोविड 19 के कारण गांवो में श्रमिकों का बढता हुआ पलायन,उससे उत्पन्न समस्याओं का मूल्यांकन,उनके समायोजन की समस्या और गांव में रोजगार के बहुआयमी समाधान तथा गांव को आत्मनिर्भर गांव बनाने के विभिन्न उपायों पर विचार प्रस्तुत करना है।

मुख्य शब्द :

आत्मनिर्भर भारत, गॉव, प्रवासी मजदूर, रोजगार, जैविक खेती।

प्रस्तावना :

कोरोना वायरस का जन्म चीन के वुहान प्रान्त मे दिसंबर 2019 में हुआ। पर चीन ने उसे पूरी दुनिया से छिपाये रखा। जब वुहान मे समस्या ने विकराल रूप लेना शुरू किया तब विश्व के सामने वायरस का राज खुल गया। देखते ही देखते ही चीन का यह वायरस दुनिया के हर देश मे पहुच गया। विश्व के महाशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, इटली, जापान, रूस जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इससे अपने को बचा न पाए। विकसित देशों के साथ

साथ विकासशील और अविकसित देश भी इसकी जद मे आ गये। यह वायरस अमीर देश में पैदा होकर हवाईजहाज से यात्रा करते हुए अमीरों के द्वारा ही विश्व के हर देश में पहुंच गया। लेकिन अब इसने समाज के हर वर्ग को अपनी चपेट में ले लिया। सभी देशो को इस वायरस से बचाव के लिए एक मात्र तरीका शारीरिक दूरी बनाये रखना आवश्यक हो गया जिसके लिए लाक डाऊन जैसा कठिन निर्णय लिया गया! अगर भारत के संदर्भ में देखे तो जनवरी 2020 को कोरोना वायरस का पहला मरीज केरल राज्य मे मिला। तत्पश्चात भारत के अन्य राज्यो में देखते ही देखते इसने महामारी का रूप धारण कर लिया। मार्च मे विश्व स्वास्थ संगठन ने इसे एक वैश्विक महामारी घोषित किया तब भारत ने अपने लोगो को बचाने के लिए 22 मार्च 2020 को एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगाया। उसके बाद 25 मार्च से 13 मई तक कई चरणों में लाक डाऊन लगाया ताकि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सके।

लॉकडॉउन ने वैश्विक स्तर पर समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित किया जिसमें आर्थिकी को इस कदर ध्वस्त कर दिया है कि कोई भी राष्ट्र इस महामारी के कारण अपनी अर्थ व्यवस्था को नही सम्भाल पा रहा है। लाक डाऊन के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी हैं। देश की गिरती हुई अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने मई महीने मे अनलाक वन शुरू किया जिससे लोग वापस काम पर लौट सके। लेकिन संक्रमण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इस समय सरकार के सामने चुनौती है की संक्रमण पहले रोके कि अर्थ व्यवस्था को सम्भाले। सरकार ने जान है तो जहान है का नारा दिया। पर इस दौर मे यह भी समस्या विकट रूप से खडी हो गयी की हर तरह के काम धंधे बन्द होने से और उत्पादन के न होने से विभिन्न राज्यो से कुशल और अकुशल श्रमिकों का पलायन शुरू हो गया। जो जहा है वही रहे का सरकार का ऐलान कामयाब नही हो सका।

कोरोना से लाक डाऊन मे सबसे बडी समस्या यह उभरी कि जो लोग रोज कमाते थे फिर शाम के भोजन का प्रबन्ध करते थे उनके सामने खाने की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी। प्रथम लाकडाऊन तक तो सरकार ने जरूरत मंदो को भोजन का वितरण किया पर केवल इससे ही उनकी जरूरतें पूरी नही हो पा रही थी।

जब लाक डाऊन और आगे बढ़ा तब शुरू हुआ तब देश के हर प्रदेश मे निवास करने वाले मजदूरो का असली पलायन और तब देखा गया उनके धैर्य का टूटना। एक तो भोजन की समस्या, दूसरे आर्थिक असुरक्षा और तीसरा बढ़ते संक्रमण के भय के कारण श्रमिक अपने घर परिवार तक किसी भी हाल में पहुंच पाने की जददोजहद में लग गए। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, और कर्नाटक आदि प्रदेशो के मजदूर घर वापस जाने के लिए सड़क पर आ गए। तब न तो ट्रेन चल रही थी न बसे। असहाय मजदूर परिवार के सदस्यों के साथ पैदल ही चलना शुरू कर दिये। फिर सरकार द्वारा मजदूरो को उनके गृह जनपदो मे भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन व बसो का संचालन शुरू करना पडा था। इस तरह करीब दस से बारह करोड मजदूर अपने घरो को पहुंचाए गए। लॉक डाउन की स्तिथि अब भी है अलग अलग राज्यो में अलग अलग तरह से। यहाँ पर सरकार की नीति नियत गलत हुई. क्योंकि सम्भवतः मजदूरों को लॉकडाउन करने से पहले उन्हे अपने गंतव्य तक पहुंचा देना चाहिए था।

अब प्रश्न यहाँ यह उठता है क्या जो मजदूर वापस गाँव को चले आये है बिना उनके उधोगो मे उत्पादन शुरू हो पायेगा? क्या मजदूरों को पुनः उन्ही स्थानों में रोजगार मिलेगा? पुनःदेश की अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या नीति बनेगी? इसका जबाब तो कोरोना समाप्त होने के बाद ही खोजा जायेगा। पर जो यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ मे मजदूर घरों को आये है उनको गावों मे रोजगार मिल पाये इसको सुनिश्चित कैसे किया जाए, ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है।

वैसे भी भारत कृषि आधारित समाज है और सुखद तो यह रहा कि इस कोरोंना काल में भी और बड़ी से बड़ी आपदा आने पर भी भोजन को लेकर समस्या नहीं हुई क्योंकि भोजन ही सबकी मूलभूत आवश्यकता है। सब कुछ बन्द था लेकिन किसान कि खेती नहीं रुकी। तो क्यों न फिर से गांव की ओर रुख किया जाए और कृषि पर विशेष ध्यान देकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया जाए।

गावों मे कृषि के क्षेत्र मे बहुत कम रोजगार है पर बस उन्ही के लिए काम है जो पहले से गाँव मे रह रहे है। तो नये पहुचे मजदूरो को रोजगार कृषि के क्षेत्र मे अभी तो न के बराबर है। यह भी अब नये सिरे से सोचने

की जरूरत है कि गावों मे लोगो को किस काम से रोजगार वर्ष भर उपलब्ध हो सकता है?

एक आँकडे के अनुसार आज 50 से 52 करोड लोग बेरोजगार हो गये है।इस दौरान0श्6 लोगो को कृषि के क्षेत्र मे रोजगार मिला है। पर कामोवेश यह स्थिति एक साल तक रही तो फिर कैसे लोगो को रोजगार दिया जायेगा।

भारत के लघु व मध्यम उघोगो की कमर तो टूट चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रो मे कुटीर उघोग है नही। फिर रोजगार के नये अवसर कैसे पैदा होगे, इस पर सरकार निरन्तर विमर्श कर रही है। अभी तो पहले से स्थापित मनरेगा में सरकार हर मजदूर को काम तो दे रही है सौ दिन का। पर यह सौ दिन क्या उनके भरण पोषण के लिए काफी होगा? तो शायद नही।

जैसे जैसे कृषि का आधुनिकीकरण व मशीनीकरण होता गया गाँव मे रोजगार के अवसर कम होते गये। अब जब कोविड–19 के कारण श्रमिक अपने गाँव लौट रहे है तब उनको समायोजित करने के लिए पुनः रोजगार के अवसर कृषि मे टिकाऊपन लाकर उपलब्ध कराया जा सकता है। गांव के विकास को विमर्श के केंद्र में लाना है। परम्परागत ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान का समावेश करके ही कृषि मे टिकाऊपन लाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रो मे निवेश करना आवश्यक है जो की भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा किया है। उत्तर कोरोना काल में आत्मनिर्भर गाँव बन सके इसके लिए निम्न बिन्दुओं पर विचार करना होगा।

- गाँवो के स्वरूप मे अब बदलाव की जरूरत है जिससे गाँव स्मार्ट गाँव (smart village)बन सकता है। कुछ बुनियादी सुविधाओ (infrastructure) को उपलब्ध करा कर गाँवो को स्मार्ट गाँव मे बदलकर रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो सकते है जैसे गाँव मे कम से कम बीस घन्टा बिजली, पानी, स्वास्थय की सुविधा, शिक्षा व्यवस्था, यातायात सुविधा, इन्टर नेट केबल आदि। रूवर्न (ruburnization) से शहरो की कुछ सुविधाएँ भी गाँव मे बन जाये जो पहले से नही है।
- आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण औघोगिकीकरण के माध्यम से बडे पैमाने पर रोजगार का सृजन करना।
- गाँव में ही अच्छे शिक्षण और तकनीकी संस्थान को बनाना होगा ताकि युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिससे नगरो में जनसंख्या का पलायन रोक जा सके।
- आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। पांच से दस पंचायतों के समूहों का एक बडा समूह (cluster approach) बनाकर कृषि आधारित उद्योगो (Agro industry) को लगाना होगा। जिससे कृषि व उसपर आधारित रोजगार का सृजन करके गाँव के लोगो को गाँव मे ही रोजगार दिया जाये।
- जो लोग तकनीकी रूप से सक्षम है जैसे कम्प्यूटर बनाना, बिजली, प्लम्बर कारपेंटर आदि उनको अपना करोबार शुरू करने के लिए मदद हो सके।
- उत्पाद की ब्रांडिंग के साथ देशी व विदेशी बाजार मे उनकी माँग को बढाने के नये तरीकों को तलाशने होगे। बाजार अर्थव्यवस्था पर चिंतन करना होगा। वैश्विक समीकरण को कैसे प्रभावित करे इस पर विचार करना होगा।
- गावो मे लोगो को खेती के लिए स्वदेशी तकनीकी (indigenous technology)को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जिससे लोगो को कम खर्च मे अधिक आय मिल सके और दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम हो।
- ए पी एम सी के वर्तमान कानुन को नये बाजार की जरूरत को देखते हुए पुनः संशोधित करने की जरूरत है। जिससे किसानो और उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।
- अब पुनः जैविक खेती की आवश्यकता महसूस होने लगी है। जैविक खेती से किसान व गाव आत्म निर्भर बन सकता है। जैविक खेती मे गोवर के खाद की बहुत मात्र मे जरूरत है। अगर किसान के पास खुद गोबर की खाद है तो बाहर से खाद खरीदने की जरूरत नही होगी।

- जैविक तरीके से खाघान्नो का सर्वाधिक उत्पादन करके खाघान्नो के निर्यातको बढावा देकर गाव को आत्म निर्भर बनाना।
- कृषि के क्षेत्र मे उत्पादन और उत्पादकता मे टिकाऊ पन लाने के लिए सिंचाई, जैसे फौब्बारा विधि, टपक सिचाई विधि मिट्टी परीक्षण समन्वित कीट प्रबन्ध तथा समन्वित पोषकतत्वो की तकनीकी को अपनाने की जरूरत है।
- गावों मे शीत गृहों का निर्माण को बढावा देने की जरूरत है जिससे कि यदि उत्पाद का सही मूल्य नही मिल रहा है तो किसान उसको शीत गृह मे सुरक्षित रख सके, तथा जब बाजार मे सही मूल्य मिले तो बेच दे।
- संरक्षित खेती को गावों मे बढावा देकर किसानो की आय मे वृद्धि के साथ साथ लोगो को रोजगार भी मिलेगा।
- आवागमन के साधनों को बढाकर गाँवो मे उघोगो को सुगम बनाया का सकता है।
- उत्पाद को बडे बडे शहरो मे जल्दी व सुरक्षित पहुँचाने के लिए अच्छी सडके और वाहनों को बढावा दिया जाये ।
- गाँवों मे लोगो को आत्म निर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि जैविक खेती के साथ साथ पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हर किसान के पास खेती की भूमि के अनुरूप पशु हो तो उनको आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सकते है। सबसे छोटे व सीमान्त किसानो तथा भूमि हीन कृषक मजदूरो को बकरी, भेड पालन मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन को बढावा देकर नए रोजगार और आय के साधन को पुनः जीवित करने की जरूरत है।
- बीजो का भण्डारण, बीजो का चयन और खर पतवार नाशको का नियंत्रण व कीडो की रोकथाम मे आज भी बहुत से किसान अपने पुरातन परम्परागत स्वदेशी ज्ञान का उपयोग कर रहे है। यह हमारे ज्ञान की आत्म निर्भरता है जो आज भी एक पीढी से दुसरी पीढी मे हस्थानांतरित हो रही है लेकिन आधुनिकता के साथ यह कम होता जा रहा है। आज के युवा किसानों को दोनो के मिश्रण का प्रयोग करना चाहिए है।
- आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए उन्ही चीजों के उत्पादन पर बल देना होगा जो अति आवश्यक हो। अनावश्यक बस्तुओ को कम से कम बनाए। प्रकृति आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती है लेकिन लालसा का समाधान कोई नहीं कर सकता। उपभोग समाज का सृजन भी प्रकृति के दोहन से हुआ है। इस पर नियंत्रण की जरूरत है।
- स्मार्ट विलेज बनाने के लिए मुखर होना पड़ेगा और वोकल फॉर लोकल पर बल देना होगा। स्थानीय स्तर पर खान पान, औषधियां जड़ी बूटियों, तुलसी गिलोय की खेती से आय और रोजगार की बहुत सम्भावना है। इसे अब बढ़ाने की जरूरत है।
- खाद्य प्रसंस्करण (food processing) की स्थापना से गावों मे रोजगार बढेगा। साथ मे उत्पादन करने वाले किसानो की आय मे बृद्धि होगी। फल और सब्जी प्रसंस्करण को बढावा देना होगा। जिससे खेत से बाजार तक जो उत्पाद की हानि होती है उसे कम किया जाये। देश मे केवल 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक अभी फलो और सब्जियों का डिब्बा बन्द प्रसंस्करण होता है इसको 60 प्रतिशत तक ले जाने की जरूरत है।
- कामर्शिय फसलो जैसे मूंगफली ,सूरजमुखी की उत्पादन पर विशेष ध्यान देना होगा।
- मशरूम अपनी गुणवत्ता के कारण आज हमारे भोजन मे एक विशेष स्थान बना रहा है। मशरूम जो शहरो का महंगा खाद्यपदार्थ है आसानी से इसकी खेती करके अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकता है। जरूरत है तो किसानो और युवाओ को कुशल प्रशिक्षण की जो कृषि विश्वविघालयो मे आसानी से उपलब्ध है।
- कृषि उत्पादन के साथ साथ उत्पादित पदार्थो की पैकेजिग, वितरण व विपणन पर भी ध्यान देना होगा। जिससे आत्म निर्भर गाँव से नये आत्म निर्भर भारत की अवधारणा को साकार किया जा सकता है।

- कृषि मे निवेश को बढाने के साथ साथ गावों मे आधुनिक भण्डारण की सुविधा बनाना होगा जिससे किसान अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर सके।
- गावों को आत्म निर्भर बनाने के लिए गावों मे कुटीरउघोगो को पुन प्रारम्भ करना होगा जैसे खादी, खाडसारी मिल, छोटी दाल मिल, मसाले बनाने के उघोगो और हथकरघा को पुनः शुरू करे।
- कपडा उघोगो का आधुनिकी करण, जूट उघोगो को बढाना, बांस की लकड़ी के उद्योग, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, फल उत्पादन व्यवसायों को भी गांव स्तर पर विकसित व प्रशिक्षित करने की जरूरत है।
- गाँव में गए श्रर्मिको को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना होगा और गांव को नए नगर में बदलना होगा ताकि पलायन रोका जा सके।
- अब गाँवों को स्मार्ट गाँव बनाने की जरूरत है जहा पर स्वास्थय की बुनियादी सुविधा हो ताकि जनसंख्या का पलायन न हो।
- गाँव मे अब स्किल मैपिग करके यह पता करना होगा कि गाँवों मे किस तरह के कुशल कामगार उपलब्ध है और उनको किस तरह के रोजगार मे लगाना होगा या देना होगा।
- ग्रामीण रोजगार को बढाने के लिए गाँवो मे मध्यम व लघु उघोगो को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल को ध्यान मे रख कर ही स्थापित करना होगा जिससे उत्पादन लागत कम हो और उचित लाभ मिले सके।
- गावों मे लोगो को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकारी बैक या सहकारी बैंको को खोलना व सुदृढ करना पडेगा।
- सहकारी खेती को बढावा देना होगा कारण कि अब गावों मे बहुत कम लोग है परिवार के सदस्य इस अवस्था मे नही है कि वह खेती कर सके तो जरूरत है गावों मे सहकारी खेती को शुरू किया जाये जिसमे हर सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित हो। और लाभ खेती के क्षेत्रफल के आधार पर बांटा जाये।
- इस तरह के कार्यो को गावों मे कृषि स्नातक व अन्य पढे लिखे युवाओं को प्रोत्साहित करके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर नये सिरे से विमर्श करने की जरूरत है जिससे गावों से हो रहे मजदूरो के पलायन को गावों मे रोक दिया जाये। महात्मागान्धी जी कहते थे भारत की आत्मा गावो मे बसती है। अगर विकसित और सुन्दर व गौरव शाली आत्म निर्भर भारत देखना चाहते है। तो पहले गावों का विकास जरूरी है। पर योजना आयोग 1952 मे बना तो वह गाव को भूल गया और उसकी प्राथमिकता शहरो के जविकास की हो गयी। वह शहरो मे ही सुख सुविधा के साधनों को जुटाने मे लगा रहा। परिणाम स्वरूप गाँव बद से बदतर होते गये। गावों से रोजगार के लिए शहरो की ओर पलायन होना शुरू हो गया देखते देखते शहर महानगर बनते गये। छोटे शहर बडे शहरो मे बदल गये। शहरो मे मलिन बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों का एक नया देश बन गया। पूर्व राष्ट्रपति डॉ कलाम जी का PURA (Provision of Urban Amenities in Rural Areas) की विचारधारा को साकार रूप दिया गया होता तो निश्चित ही आज इस संकट का सामना न करना पड़ता। हाल में ही 2014 में माननीय प्रधानमत्री जी द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बैन मिशन भी बनाया गया जिसमें गांव के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है।

देश कोरोना के संकट से उबर जायेगा परन्तु आगे भी जब सब कुछ सामान्य हो जाए तब भी सरकार को समाज को अपने गांव की सुदृढता बनाए रखना होगा।

गावो मे कृषि आधारित उघोगो की पहचान कर और समयबद्ध तरीके से हल कर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है। भारतीय योजनाकारों और नीति निमार्ताओ ने हमेशा ग्रामीण क्षेत्रो के विकास की अनदेखी की है वह शहरी औधोगिक करण पर विशेष बल देते रहे है। उत्तर कोरोना मे सरकार विभिन्न केन्द्रीय योजनाओ मेक इन

इन्डिया, स्टार्ट अप ईन्डिया आत्म निर्भर भारत जैसे नवीनप्रयासो के द्वारा गावों मे आधुनिक कृषि औधोगिक आधार भूत संरचना सुनिश्चित करने की पहल कर रही है।स्वस्थ, स्वच्छ, सशक्त, समृद्ध सम्पन्न और सुंदर समाज तभी बनेगा जब सही इरादा, समावेशन, निवेश, बुनियादी ढांचा और नमोन्वेश शामिल होगा। है। अब हमको गांव के लिए कुछ नये सकारात्मक बदलाव पर बराबर काम करना होगा ताकि हम ''ओल्ड नार्मल'' की तरफ न वापस हो जाये,बल्कि सबको साथ लेकर ''न्यू नार्मल'' को अपना कर स्मार्ट गांव बना सके।

सन्दर्भ सूची :

1. *https//ww.ncbi,nlva.nih.gov.pmc, Creating Good Employment Opportunities for the Rural Sector,NCBI*
2. *www.economics disscusssion.net, Extra Employment Opportunities in Rural Areas- Economic Disscussion*
3. *https//www.mygov.in group-issue, Creating Better Job Opportunities in Rural India.*
4. *Kumar, Rajiv and Singh, Srijan Pal (2020), India Needs a New Rural-centric Development. Model., 24 june 2020, www.hindustantimes.com.*
5. *Kalam, A P J Abdul and Rajan, Y S (1998), India 2020: A Vision for the New Millennium Penguin India.*
6. *Gandhi, Mahatma (1927), An Autobiography: The story of My Experiments with Truth Navajivan Publishing House,Ahmedabad, India,*
7. *Prabhu, Pingali (2017), Agriculture and Rural Development in a Globalizing World: Challenges and Opportunities, Routledge.*

****